माननीय ए.एल. बाहरी और वी.के. बाली, जे.जे. के समक्ष।

मांगे राम,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 12237।

13 दिसंबर 1991.

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226-पदोन्नति-याचिकाकर्ता को पिछले दस वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नति वेतन और वेतनमान से वंचित किया गया-1973 के निर्देशों के आधार पर राज्य की कार्रवाई को खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रावधान है कि पदोन्नति रोकने के लिए निंदा या चेतावनी पर विचार नहीं किया जाएगा। .

ए एल बहरी, जे.

माना गया कि अनुलग्नक आर-एल 19 जुलाई 1973 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं जो विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि निंदा या चेतावनियां जो बड़ी सजा नहीं थीं उन्हें पदोन्नति रोकने के लिए नहीं माना जाएगा और इन दंडों को केवल कुल रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए . इन निर्देशों के मद्देनजर, इस प्रकार 1977 या 1979 में दी गई चेतावनियाँ जो प्रासंगिक समय यानी 1 जनवरी 1986 को पुरानी थीं, जब याचिकाकर्ता को उच्च पदोन्नति ग्रेड में रखने के सवाल पर विचार किया जाना था, पर विचार नहीं किया जा

सका। . अन्यथा, याचिकाकर्ता के नवीनतम रिकॉर्ड ने उसे उच्च ग्रेड में रखे जाने से वंचित नहीं किया है।

(पैरा 3)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार।

प्रतिवादियों की ओर से राजन गुप्ता, डीएजी, हरियाणा।

न्याय

A. लोक निर्माण विभाग, पानीपत में कार्यरत जूनियर इंजीनियर मांगे राम ने इस रिट याचिका में 1 जनवरी, 1986 से उस तारीख से 1640-2900 रुपये के उच्च वेतनमान में रखे जाने का निर्देश देने की मांग की है, जब उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को वहां रखा गया था, -आदेश दिनांक के अनुसार 23 मई, 1988 (अनुलग्नक पी-3)। इस विषय पर निर्देश अनुलग्नक पी-1 में दिए गए हैं। कनिष्ठ अभियंताओं के 50 प्रतिशत पदों को 1640-2900 रुपये के पदोन्नति वेतनमान में रखा जाना था और शेष 50 प्रतिशत को 1400-2300 रुपये के वेतनमान में रखा जाना था।

B. लिखित बयान में उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए रुख के अनुसार, याचिकाकर्ता को पदोन्नति ग्रेड से वंचित कर दिया गया क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ थीं। उनके मामले पर अन्य लोगों के साथ विचार किया गया और अन्य लोगों को पदोन्नत किया गया। 21 मई, 1973 को जारी राज्य सरकार के निर्देशों (अनुलग्नक आर-III) पर भरोसा रखा गया है।

C. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने पाया कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति वेतनमान देने से इनकार करने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई नियमों या निर्देशों द्वारा समर्थित नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 1977-79 के वर्षों में याचिकाकर्ता को चेतावनियाँ दी गई थीं और कमी के कारण उससे कुछ वसूली भी की गई थी, जैसा कि कहा गया है। याचिकाकर्ता को दी गई एक और

सज़ा भविष्य में प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की थी। अनुलग्नक आर-एल 19 जुलाई 1973 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं जो विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि निंदा या चेतावनियां जो बड़ी सजा नहीं थीं उन्हें पदोन्नति रोकने के लिए नहीं माना जाएगा और इन दंडों को केवल कुल रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए। इन निर्देशों के मद्देनजर, इस प्रकार 1977 या 1979 में दी गई चेतावनियाँ जो प्रासंगिक समय यानी 1 जनवरी 1986 को पुरानी थीं, जब याचिकाकर्ता को उच्च पदोन्नति ग्रेड में रखने के सवाल पर विचार किया जाना था, पर विचार नहीं किया जा सका। . इसी तरह दी गई अन्य सजा पर विचार नहीं किया जाना था। अन्यथा, याचिकाकर्ता के नवीनतम रिकॉर्ड ने उसे उच्च ग्रेड में रखे जाने से वंचित नहीं किया है।

D. जब सेवा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक उच्च वेतनमान और दूसरा कनिष्ठ वेतनमान, तो वरिष्ठता-सह-योग्यता के नियम को ध्यान में रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति को स्वचालित रूप से उच्च वेतनमान मिलेगा यदि उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में कुछ भी बुरा नहीं है। . कई व्यक्तियों द्वारा अपने रिकॉर्ड की तुलना करने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

E. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, याचिकाकर्ता को 1 जनवरी, 1986 से उस तारीख से 1640-2900 रुपये के पदोन्नति उच्च वेतनमान में रखा जाएगा, जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा